विचार

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली। सोमवार, 19 अगस्त 2019

दुनिया हमारे साथ

जम्मू-कश्मीर के मामले को लेकर संयुक्त राष्ट्र में भारत को घेरने की पाकिस्तान और चीन की कोशिश नाकाम रही। सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने इस मुद्दे पर औपचारिक बैठक बुलाए जाने के पाकिस्तान के अनुरोध को तो ठुकरा ही दिया, इस पर कोई अनौपचारिक बयान भी जारी नहीं किया। शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में अनुच्छेद 370 को खत्म किए जाने पर हुई अनौपचारिक बैठक में चीन को छोड़कर सभी देश भारत के साथ खड़े रहे। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी राजदूत सैयद अकबरुद्दीन ने मीडिया से बातचीत में साफ कहा कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना भारत का आंतरिक मामला है। कश्मीर पर लिए गए किसी भी फैसले से बाहरी लोगों को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जेहाद के नाम पर पाकिस्तान हिंसा फैला रहा है। अगर वह भारत से बातचीत चाहता है तो पहले उसे आतंकवाद फैलाना बंद करना होगा। हालांकि पाकिस्तान इस पर भी अपनी पीठ थपथपा रहा है। वह इसी बात से गदगद है कि कश्मीर पर यूएन में चर्चा हुई। हालांकि इस चर्चा को राजनयिक स्तर बहुत तवज्जो नहीं दी जाती। हाल के वर्षों में इस तरह की अनौपचारिक चर्चा का चलन बढ़ गया है जिनमें सुरक्षा परिषद के सदस्य बंद कमरे में बातचीत करते हैं और आधिकारिक तौर पर इसकी कोई जानकारी बाहर नहीं आती है। सचाई यह है कि यूएन के लिए अब कश्मीर कोई गंभीर मुद्दा नहीं रह गया है। इस पर आखिरी अनौपचारिक मीटिंग 1971 में और आखिरी औपचारिक या पूर्ण बैठक 1965 में हुई थी। पाकिस्तान इस बात को स्वीकार ही नहीं कर रहा कि विश्व बिरादरी उसकी तरह नहीं सोचती। उसने कई मुल्कों को मनाने की कोशिश की पर उसे निराशा हाथ लगी। यूएनएससी में चर्चा से ठीक पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के साथ फोन पर लंबी बातचीत की मगर कोई फायदा नहीं हुआ। आज पाकिस्तान के साथ अगर चीन खड़ा है तो उसके पीछे उसकी मजबूरी है। चीन ने पाकिस्तान में करोड़ों का निवेश कर रखा है इसलिए वह उसे संतुष्ट रखना चाहता है। वैसे कई विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान ने मामले को सुरक्षा परिषद में ले जाकर अपने लिए मुसीबत मोल ले ली है। उसे सुरक्षा परिषद द्वारा मानवाधिकारों को लेकर बने नियमों का पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भी पालन करना होगा। ऐसे में गिलगित और बल्टिस्तान को लेकर पिछले साल आए पाकिस्तानी कानून को भी झटका लग सकता है। बहरहाल इस मुद्दे पर कूटनीतिक जीत के बाद सरकार को अपना ध्यान जम्मू-कश्मीर के लोगों के साथ किए अपने वादे को पूरा करने में लगाना होगा। साथ ही वहां सुरक्षा को लेकर भी मुस्तैद रहना होगा क्योंकि खीझ में पाकिस्तान कोई नापाक हरकत भी कर सकता है। सच यह है कि जम्मू-कश्मीर में ज्यों-ज्यों विकास की प्रक्रिया तेज होगी, पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और भी एक्सपोज होता जाएगा।

हमारा जम्मू
कश्मीर

जम्मू-कश्मीर का मसला

लोगबाग

बचपन में बाढ़

संजय कुंदन

इन दिनों कई राज्य बाढ़ की चपेट में हैं। हर साल की तरह बिहार का भी यही हाल है। इसके कई जिलों में बाढ़ का पानी घरों में घुसा हुआ है। बिहार के प्रायः हर व्यक्ति के पास बाढ़ से जुड़ा कोई न कोई किस्सा या प्रसंग जरूर होता है। वहां के लोगों को इस विपदा के साथ जीने की आदत सी हो गई है। मैंने प्रत्यक्ष रूप से बाढ़ तो नहीं झेली पर उसकी परोक्ष उपस्थिति को महसूस कर चुका हूं वह भी बचपन में। हालांकि बचपन में किसी संकट का अहसास उस तरह से नहीं होता जिस तरह अधेड़ावस्था में होता है। उस समय संकट भी बड़ा रूमानी लगता है। अब जैसे एक बार पटना पर बाढ़ का खतरा मंडराया। कुछ मोहल्लों में पानी घुस गया लेकिन मेरा मोहल्ला उससे बचा रहा। जब मैंने सुना कि आसपास पानी आ गया है तो मैं बहुत दुखी हुआ। मैं सोच रहा था कि काश, हमारा घर भी बाढ़ में डूब जाता तो बड़ा मजा आता। मैंने सुन रखा था कि लोग छतों पर रहने चले जाते हैं और हेलिकॉप्टर से गिराए जाने वाले फूड पैकेट्स पर समय काटते हैं। मैं इस जीवन को जीना चाहता था। मैंने जब दुखी होकर पिताजी से कहा कि हमारे इलाके में बाढ़ क्यों नहीं आई, तो वे नाराज हो गए। फिर उन्होंने समझाया कि यह सौभाग्य है कि हमलोग बच गए वर्ना बहुत तकलीफदेह हालात से गुजरना पड़ता।

खैर, बाढ़ में वक्त गुजारने की मेरी इच्छा आगे भी पूरी नहीं हुई क्योंकि उसके बाद से अब तक पटना में बाढ़ नहीं आई। हां, कॉलेज के दिनों में कुछ संगठनों के साथ मिलकर बाढ़ पीड़ितों के लिए सहायता राशि इकट्ठा करने का अवसर जरूर मिला। मैं एक रिक्शे पर बैठकर माइक पर लोगों से बाढ़ पीड़ितों के लिए पैसे देने की अपील करता और मेरे दोस्त व संगठन से जुड़े लोग डिब्बे लेकर चलते रहते थे। डिब्बा बंद होता था। उसके ढक्कन में एक छेद किया रहता था, जिसमें लोग पैसे डालते रहते थे। बाढ़ खत्म होने के बाद जब गांव से कोई रिश्तेदार आते तो मैं उनके सामने बाढ़ के प्रसंग छेड़ देता। कई किस्से सामने आते। एक बार हमारे एक संबंधी ने गांव के एक व्यक्ति के रातोंरात अमीर हो जाने की बात बताई तो मैं चौंक गया। उन्होंने कहा कि बाढ़ कुछ लोगों को बर्बाद करती है तो कुछ को राजा भी बना देती है। दरअसल गांव के एक सज्जन ने पानी में बहता हुआ एक बक्सा पाया जो सोने के गहनों से भरा था। पता नहीं बात में कितनी सचाई थी। उन्हीं महोदय ने यह भी बताया कि एक निःसंतान औरत को एक बच्चा भी मिल गया जो एक छोटी सी चौकी पर बहता हुआ कहीं से आ रहा था।

एकदा

ककड़ी का कड़वापन

एक बार संत तुकाराम से मिलने उनके गांव के कुछ लोग आए। उन्होंने तुकाराम जी के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए उनसे प्रार्थना की, 'हमलोग तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलने की कृपा करें।' तुकाराम जी ने असमर्थता प्रकट की और एक गठरी देते हुए हुए कहा, 'इसमें कुछ ककड़ियां हैं। तुमलोग जिन तीर्थ स्थानों पर जाओ, उन स्थानों पर इन्हें नदी या तालाब में डुबा कर स्नान करवा देना। फिर इसे वापस ले आना।' तीर्थ यात्रा के दौरान उन लोगों ने वैसा ही किया। वे भगवान का स्मरण करते हुए जिस नदी में स्नान करते, उस पोटली में बंधी हुई ककड़ियों को भी डुबाकर निकाल लेते। तीर्थयात्रा से गांव लौटकर उन्होंने तुकाराम जी को ककड़ियों की पोटली लौटा दी।

तुकाराम जी ने उन सब को दूसरे दिन भोजन के लिए अपने घर आमंत्रित किया। तुकाराम जी ने उन ककड़ियों की सब्जी बनवाई और उसे भोजन में परोसा। भोजन करने के बाद सब एक ही स्थान पर बैठ गए। तुकाराम जी ने पूछा, 'तुमलोगों ने ककड़ियों को इतने तीर्थ स्थानों पर स्नान करवाया। उसके कड़वेपन में कोई फर्क पड़ा? उन्होंने उत्तर दिया, 'नहीं महाराज, ककड़ियों के कड़वेपन में कोई अंतर नहीं आया।'

तुकाराम जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, 'इतने तीर्थ स्थानों पर स्नान करके, इतने मंदिरों में जाकर भी ककड़ियां कड़वी ही रहीं। ककड़ियों ने कड़वेपन का सहज गुण त्यागा नहीं। इसी प्रकार तीर्थ यात्रा करने के बाद भी लोग वैसे के वैसे बने रहते हैं। तीर्थ यात्रा करने पर भी जब लोगों के दुर्गुण छूटे ही नहीं, तो सारी तीर्थ यात्रा व्यर्थ है। तीर्थ यात्रा से मनुष्य की बुद्धि का विकास होना चाहिए। उसके मन में परिवर्तन आने चाहिए। उसे शुद्ध और निर्मल बनाने के लिए ही तीर्थ यात्राएं रखी गई हैं। किंतु लोगों ने तीर्थ यात्रा को विनोद यात्रा में परिवर्तित कर दिया है, जो सही नहीं है।'

संकलन : **दीनदयाल मुरारका**

और पढ़ने के लिए देखें www.ekda.nbt.in

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के अधिकार और शक्तियों को लेकर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं

अब भारतीय सेना को मिलेगा प्रधान सेनापति

रंजीत कुमार

भारत की तीनों सेनाओं के एक प्रधान सेनापति यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) की नियुक्ति का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से किया, जिसका सामरिक हलकों में व्यापक स्वागत हुआ है। दो दशकों से इस मसले पर बहस छिड़ी हुई थी, लेकिन कोई आम राय नहीं बन पाने की बात कर अब तक की केंद्र सरकारें इसे टालती रही थीं। सियासी तबके में आशंका थी कि प्रधान सेनापति के हाथ में कहीं इतनी ताकत और अधिकार न सौंप दिए जाएं कि एक दिन वह राजनीतिक सत्ता के लिए ही खतरा पैदा कर दे। इस आशंका को बल तब मिला था जब 16 जनवरी, 2012 की रात को केंद्र सरकार को सूचित किए बिना तब के सेनाध्यक्ष जनरल वीके सिंह ने सेना की दो बटालियनें दिल्ली की ओर कूच करवा दी थीं। रातोंरात जब सेना की दो यूनिटों को दिल्ली पहुंचने से पहले रक्षा सचिव के आदेश से रोका गया तब सेना मुख्यालय ने आरोपों से बचने के लिए कहा था कि यह एक अभ्यास मात्र था।

ओहदे पर विवाद

प्रधानमंत्री ने सबसे बड़े सेनाधिकारी के मुख्यालय का एक ब्लूप्रिंट तैयार करने के बाद ही दूरगामी महत्व के इस फैसले की घोषणा की होगी। तीनों सेनाओं के साझा प्रधान का पद बना कर उसके लिए केवल एक कुर्सी की व्यवस्था ही नहीं करनी होगी बल्कि इससे जुड़े संपूर्ण रक्षा महकमे में आमूल बदलाव लाना होगा। पीएम ने यह साफ नहीं किया है कि प्रधान सेनापति फाइव स्टार रैंक वाले होंगे या वह पद फोर स्टार ही रहेगा। फिलहाल तीनों सेनाओं के मौजूदा सेना प्रमुख फोर स्टार रैंक के होते हैं। इसलिए प्रधान सेनापति कितना प्रभावी साबित होगा, यह बहुत कुछ फोर या फाइव स्टार रैंक पर भी निर्भर करता है। सीडीएस की सिफारिश 1999 में करगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेनाओं में समुचित तालमेल की व्यापक कमी महसूस होने के बाद की गई थी और इसी से सबक लेते हुए वाजपेयी सरकार ने चार मंत्रियों का जो समूह गठित किया था उसने करगिल समीक्षा समिति की सिफारिशों पर मुहर लगाते हुए सीडीएस का पद बनाने की अनुशंसा कर दी थी। इसके बाद सबसे पहले तो तीनों सेना प्रमुखों में आपसी मतभेद उजागर हुए जब खासकर वायुसेना मुख्यालय ने इसका इस नजरिए से विरोध किया था कि सबसे बड़ी सेना होने की वजह से थलसेना का प्रमुख इस पर अपना हक जमाएगा।

> सीडीएस की सिफारिश 1999 में करगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेनाओं में समुचित तालमेल की व्यापक कमी महसूस होने के बाद की गई थी

अभी तीनों सेनाओं का एक साझा प्रमुख होता है लेकिन वह चूंकि फोर स्टार का जनरल, एडमिरल या एयर चीफ मार्शल होता है, इसलिए तीनों सेना प्रमुखों की एक संयुक्त समिति के चेयरमैन के पद पर बैठ कर वह दूसरे सेना प्रमुखों की हैसियत और अधिकार पर आंच नहीं डाल सकता है। इस पद को चेयरमैन, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी कहा जाता है। यह व्यवस्था पहले से चली आ रही है लेकिन सेनाओं में बेहतर तालमेल के लिए सरकार ने पिछले दशक के शुरू में इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ बनाया और इसका मुखिया चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ (सीआईडीएस) कहा गया। यह थ्री स्टार के रैंक वाला बनाया जाता है। तीनों सेनाओं में लेफ्टिनेंट जनरल, वाइस एडमिरल या एयर मार्शल रैंक के अधिकारी को बारी-बारी से यह पद सौंपा जाता है जिसका काम होता है तीनों सेनाओं में तालमेल बैठाने के लिए सिफारिशें करना। लेकिन कुछ अहम विभाग जैसे बैलिस्टिक मिसाइलों और परमाणु हथियारों वाले स्ट्रैटजिक कमांड या अंडमान स्थित ट्राइसर्विस कमांड को सीआईडीएस के तहत रख दिया गया है। इसके अलावा सीआईडीएस के तहत प्रस्तावित स्पेस या साइबर कमांड जैसे विभाग भी होते हैं। सीआईडीएस का दायित्व तीनों सेनाओं में तालमेल बैठाने वाले प्रस्ताव करना होता है जिसे मानना या अस्वीकार करना सेना प्रमुखों पर निर्भर करता है। सीआईडीएस के पद पर बैठा अफसर चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी (सीओएससी) को रिपोर्ट करता है। इसी चेयरमैन के पद को ऊंचा कर प्रधान सेनापति का पद बनाने का प्रस्ताव है। जब यह पद बन जाएगा और उसे तीनों सेना प्रमुखों से ऊपर का रैंक दिया जाएगा तो स्वाभाविक है कि तीनों सेना प्रमुखों को उसके निर्देशों का पालन करना होगा। इसी तरह की व्यवस्था अमेरिका में भी है जहां चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर बैठा शीर्ष जनरल सीधे राष्ट्रपति के संपर्क में रहता है और उसके आदेशों का पालन जल-थल- हवाई बलों को करना होता है। इसी तरह की व्यवस्था ब्रिटेन और चीन में भी है लेकिन भारत में जब तीनों सेना मुख्यालयों से ऊपर शासन करने वाला कोई नया दफ्तर गठित होगा तब इसके प्रमुख के ओहदे को लेकर विवाद पैदा होगा।

Bhagirath

जयपुर में 61वीं कैवेलरी रेजिमेंट के दस्ते की परेड

अधिकार और शक्ति

फिलहाल तीनों सेना प्रमुख वरिष्ठता क्रम में रक्षा सचिव से ऊपर माने जाते हैं। ऐसे में सेना प्रमुखों से ऊपर रैंक वाले सीडीएस के सामने रक्षा सचिव या कैबिनेट सचिव की क्या हैसियत होगी? क्या सीडीएस के निर्देशों का पालन रक्षा सचिव को करना होगा? क्या सीडीएस कैबिनेट सचिव को लांघ कर सीधे पीएम को अपनी सिफारिशें भेजेंगे? आपात स्थिति में पीएम अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की सलाह मानेंगे या सीडीएस की बात सुनने को बाध्य होंगे? रक्षा मंत्रालय की नौकरशाही सीडीएस की हैसियत को लेकर परेशान रही है। इसलिए विभिन्न स्तरों पर इस पद को लेकर अब तक व्यक्त शंकाओं के मद्देनजर सामरिक हलकों में यही उम्मीद की जा रही है कि इस पद और इसके कार्यालय की हैसियत साफ करने वाला प्रस्ताव विस्तृत रूप में कैबिनेट मामलों की सुरक्षा समिति के समक्ष पेश किया जाएगा। आशा है कि सीडीएस के कार्यक्षेत्र, पद, इसके अधिकार व शक्ति आदि का पूरा खुलासा सरकार जल्द करेगी। तभी पता चलेगा कि प्रधान सेनापति का पद महज दिखावटी रहेगा या इसके जरिए भारतीय रक्षा तंत्र में कोई बड़ा सुधार लाया जा सकेगा।

आज भी दफ्तरी भाषा ऐसी कि सिर पीट लें

कठिन शब्दावली केवल पुलिस प्रशासन में इस्तेमाल नहीं होती। इससे अधिक डरावने उर्दू- फारसी लफ्ज राजस्व विभाग के दस्तावेजों में देखने को मिलते हैं

नरपत दान बारहठ

हाल ही एक सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से पूछा कि एफआईआर में उर्दू और फारसी के शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, जबकि प्रार्थी या आम शिकायतकर्ता ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते। कोर्ट ने हिदायत देते हुए कहा कि ऐसे भारी-भरकम शब्दों की जगह सरल भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, जो आसानी से समझ आ सके। जिन शब्दों के अर्थ समझने के लिए शब्दकोश देखना पड़े, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल न करें। पुलिस हर तरह के लोगों के लिए काम करती है, ना कि उर्दू-फारसी में डॉक्टरेट करने वालों के लिए। लिखी हुई बातें लोगों की समझ में आनी चाहिए। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को हलफनामा दायर कर यह बताने को कहा है कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल पुलिस करती है या शिकायतकर्ता।

हालांकि यह कोई नया चलन नहीं है। शासन-प्रशासन में फारसी, अरबी और उर्दू के लफ्जों का इस्तेमाल मुगल काल से चला आ रहा है। अंग्रेजी हुकूमत के दौर में अंग्रेजी के दुरूह शब्दों का प्रचलन शुरू हुआ। यहां गौर करने वाली बात यह है कि यह कठिन शब्दावली केवल पुलिस प्रशासन में प्रयुक्त नहीं होती। इससे भी अधिक डरावनी उर्दू फारसी शब्दावली राजस्व विभाग और अदालत के दस्तावेजों में देखने को मिलती है। यह अपने आप में अजीब और अलग तरह की समस्या है। दिक्कत यह है कि संबंधित अधिकारी इस भाषा के हिंदी में सरलीकरण के किसी सरकारी आदेश के बिना इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं।

इस स्थिति से सबसे ज्यादा समस्या किसानों को होती है। खेती से संबंधित राजस्व की शब्दावली न केवल आम आदमी बल्कि अक्सर राजस्व अधिकारियों के लिए भी समझ से परे होती है। उन्हें भी शब्दकोश का सहारा लेना पड़ता है। पुलिस प्रशासन में अमूमन जो फारसी उर्दू के शब्द प्रयुक्त होते हैं वे शिकायतकर्ता के लिए तो मुश्किल पैदा करते ही हैं, वकील भी उन्हें देखकर माथा पकड़ लेते हैं। अक्सर इस्तेमाल में आने वाले फारसी और उर्दू के कुछ शब्द देखिए- मोहर्रिर, इमरोज, तहरीर, पुलंदा, हजा, मजरूब, जरायम, दीदा दानिस्ता, पेशबंदी, मसरुका...। इनके अर्थ पता करना शिकायतकर्ता के लिए किसी सजा से कम नहीं है। ऐसी शब्दावली से आम आदमी समझ ही नहीं पाता कि उसकी एफआईआर रिपोर्ट में आखिर लिखा क्या है।

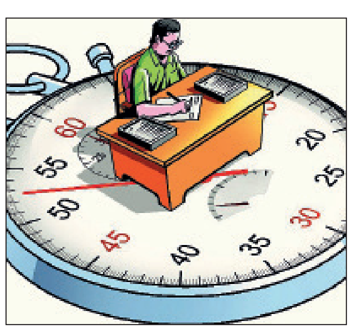

कॉमन रूम

इससे भी भयानक शब्द जाल राजस्व विभाग में है जो तकरीबन हर राज्य में कायम है। राजस्व की शब्दावली की एक बानगी देखिए - तितम्मा मिलान, वाजिब उल दर्ज, रूढ़ अलामात, मुनारा, मसाहती ग्राम, गोश्वारा, बयशुदा, साकिन, मजकूर, अखात तफसील...। ऐसे सैकड़ों शब्द आम आदमी के साथ ही पटवारियों और राजस्व अधिकारियों के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। पुराने राजस्वकर्मी थोड़ा-बहुत अर्थ जानते समझते हैं, नए कर्मचारियों को तो शब्दकोश ही खंगालना पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह कि कई शब्दों के अर्थ शब्दकोश में भी नहीं मिल पाते हैं। संबंधित राजस्व अधिकारियों को भी नहीं पता कि इन शब्दों की जगह सामान्य हिंदी शब्द कब इस्तेमाल किए जा सकेंगे।

गौरतलब है कि मुगल काल में जमीनों की पहचान करने, उसे नंबर व नाम देने की व्यवस्था अकबर के मंत्री टोडरमल ने शुरू की थी। उसमें इस्तेमाल शब्दावली करीब चार सौ साल बाद आज भी ज्यों की त्यों मजबूती के साथ राजस्व के दस्तावेजों में जमी हुई है। यहां इस बात को भी रेखांकित करना चाहिए कि ऐसे कठिन शब्द अदालत के दस्तावेजों में भी पाए जाते हैं लेकिन उनमें ज्यादातर अंग्रेजी के शब्द होते हैं जो अंग्रेजी शासन की देन हैं। हालांकि उसके साथ हिंदी अनुवाद उपलब्ध रहता है लेकिन मूल बात यह है कि हम आजादी के सात दशक बाद भी भाषाई गुलामी को ढो रहे हैं। क्यों कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया कि इन दुरूह शब्दों की जगह सरल हिंदी शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए? ऐसी कठिन शब्दावली का आम आदमी से क्या ताल्लुक? अब यह उम्मीद की जानी चाहिए कि दिल्ली हाईकोर्ट की पहल के बाद हालात बदलने शुरू होंगे।

THE SPEAKING TREE

और पढ़ने के लिए देखें

www.speakingtree.nbt.in

बाहरी साधनों पर निर्भरता भीतर से कमजोर बनाती है

हरीश बड़थ्वाल

इंजीनियरिंग पढ़ रहे, घर आए भांजे से मैंने पूछा, 'यह चार सौ ग्राम ब्रेड का पैकेट बीस रुपये का है, एक किलोग्राम कितने का हुआ?' इससे पहले कि भांजा पॉकेट से कुछ निकालता, मैंने टोक दिया, 'नहीं, बगैर कैलकुलेटर के बताना है।' लाड़ले को उलझन में देख मां ने मोर्चा संभाला, बचाव में तपाक से बोलीं, 'इसे पढ़ाई में बारबार कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ता है। बेचारे को वैसी ही आदत पड़ गई है।' सरल गणना के लिए कैलकुलेटर निकालने, सामान्य जानकारी के लिए गूगल खंगालने या तनिक दूर जाने के लिए दुपहिया उपयोग करने के अभ्यस्त, इन साधनों के अभाव में अपने अनेक कार्य सुचारू रूप से नहीं कर पाएंगे।

आज मोबाइल फोन से वंचित होना बहुतेरों को बीमार बना रहा है। इसके विपरीत जोड़ने-घटाने, दिमाग पर जोर लगा कर याद करने, यथासंभव पैदल चलने आदि गुणों का अभ्यास जारी रहेगा तो परिष्कृत होते-होते ये गुण हमारी जीवनचर्या को समृद्ध और खुशगवार बना देंगे, हम उपकरणों के गुलाम नहीं रहेंगे। एक औसत मस्तिष्क में ज्ञान और जानकारियों को संचित और संश्लेषित करने तथा नए कौशल सीखने की अपार क्षमता होती है। मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि मस्तिष्क को दीर्घावधि तक निष्क्रिय छोड़ दें तो व्यक्ति स्थायी तौर पर अकर्मण्यता का आदी हो जाता है। बरसों से प्रयोग में नहीं लाई गई उस मिक्सी या दुपहिए की याद करें जिसे एक दिन कबाड़ी के हवाले करना पड़ा। पर-निर्भरता एक विकार है और निर्भरता मन की हो तो व्यक्ति का आध्यात्मिक और बौद्धिक विकास अवरुद्ध समझा जाए।

हेलेन केलर की राय में एकल स्तर पर सीमित रूप में कुछ तो हासिल हो जाएगा किंतु उत्कृष्ट परिणामों के लिए सामूहिक स्तर पर एकजुटता से कार्य करने होंगे। दूसरों के सहयोग और सदाशयताओं के बिना उन्नति संभव नहीं। उपकरणों में कंप्यूटर और टेलिफोन के बिना हमारे अधिकांश कार्य ठप हो जाएंगे। परंतु विरोध उस मानसिकता से है जिसके चलते हम घर, समाज या कार्यस्थल के अनेक ऐसे कार्यों के लिए भी उपकरणों पर या दूसरों पर आश्रित हो जाते हैं जिन्हें हम स्वयं सहजता से पूरा कर सकते हैं। वैचारिक निर्भरता से ग्रस्त व्यक्ति में आत्मविश्वास कम होता है। आशंका और विफलता के भय से आक्रांत ऐसा व्यक्ति नए कार्य हाथ में नहीं लेता। अपनी योग्यता, कार्य या सोच के प्रति वह तब तक आश्वस्त नहीं होता जब तक उनकी स्वीकृति नहीं मिलती जिन्हें वह श्रेष्ठ मानता है। दूसरे रुष्ट न हो जाएं, इस भय से वह अपना मतभेद जाहिर नहीं करता। अकेले रहने का खयाल भी उसे भारी पड़ता है।

दूसरों के समर्थन की चाहत निर्भरता की प्रवृत्ति की चरम सीमा और व्यक्ति की अंदरुनी निर्बलता का संकेतक है। स्वयं को अंदरुनी तौर पर जितना पुख्ता बना लेंगे उसी स्तर तक बाहरी निर्भरता घट जाएगी। उपकरण हों या व्यक्ति, बाहरी तत्वों पर निर्भर रहने की प्रवृत्ति व्यक्ति को पराधीन, अकर्मण्य और अक्षम बनाती है। अहम प्रश्न है, आपकी संतुष्टि या प्रसन्नता की डोर किसी दूसरे के पास क्यों हो। आपका कृत्य उचित है इसके सत्यापन के लिए दूसरे की मुहर क्यों चाहिए? वाहवाही चाहिए तो वह आपकी अंतरात्मा की या फिर प्रभु की ही क्यों न हो।

सरकार के संकट मोचक बनते दो अफसर

विशुद्ध राजनीति
शख्सियत

संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन और श्रीनगर के डेप्युटी कमिश्नर शाहिद इकबाल चौधरी इन दिनों सुर्खियों में हैं। वैसे तो सैयद अकबरुद्दीन के लिए सुर्खियों में रहने का यह पहला मौका नहीं है लेकिन शाहिद इकबाल पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में इसलिए हैं कि उन्हें श्रीनगर में विपरीत परिस्थितियों से बहुत ही शानदार तरीके से मुकाबिल होते देखा जा रहा है। शाहिद इकबाल ने सुनिश्चित किया है कि संवादहीनता की स्थिति न बनने पाए। दोनों के बारे में बता रहे हैं **नरेंद्र नाथ**:

कुछ नया करते रहना पहचान

सैयद अकबरुद्दीन देश में नायक की तरह चर्चा में हैं। यूएन में जिस अंदाज में उन्होंने चीन-पाकिस्तान की कोशिश को अपने अंदाज से परास्त किया, उसके बाद उनकी तारीफ हो रही है। वैसे यह पहला मौका नहीं है जब उन्होंने अपनी कूटनीतिक होशियारी से भारत को बढ़त दिलाई है। पहली बार वे तब देश की नजर में आए जब वह विदेश मंत्रालय में प्रवक्ता बनाए गए। बतौर प्रवक्ता उन्होंने कूटनीतिक स्तर पर भारत का पक्ष रखने में ऐसी महारत हासिल की कि कई संजीदा मौकों पर उन्हें ही भेजा जाने लगा। उन्होंने पहली बार इस पद को अहम बना दिया। सैयद अकबरुद्दीन इंडियन फॉरेन सर्विस में 1986 बैच में आए। वह 2012-2015 के बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रहे। उसके बाद उन्हें संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। जब वह विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता थे, तब वे देर रात तक किसी भी संदेश का तत्काल जवाब देते थे। मीडिया में कोई सूचना अधूरी नहीं जाए और भारत का पक्ष मजबूती से जाए, इसके लिए वे न सिर्फ हमेशा अलर्ट मोड में रहते हैं बल्कि इनोवेशन भी करते हैं। एक बार उन्होंने कहा था कि वह प्रति दिन 300 से अधिक संदेश का उत्तर देते हैं। पिछले शुक्रवार को यूएन में उन्होंने जिस तरह पाकिस्तानी पत्रकारों से हाथ मिलाकर उन्हें निरुत्तर किया, वह भी उसी इनोवेशन वाले अंदाज का हिस्सा था। इसी साल मई में पाकिस्तान के जैश-ए-मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर को अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने में भारत ने रणनीति बनाने का काम इन्हीं को दिया था। सोशल मीडिया पर अपनी बात तुरंत और प्रभावी तरीके से रखने वाले अकबरुद्दीन ने पूरे विश्व में डिप्लोमैसी को एक नया आयाम दिया। उनके नक्शे कदम पर दूसरे देशों के प्रतिनिधियों ने इस माध्यम को अपनाया। योग दिवस को यूएन से बड़े बहुमत से मान्यता दिलाने में उनकी कूटनीतिक रणनीति अहम मानी गई। महात्मा गांधी को 185 देशों की ओर से दी गई श्रद्धांजलि का विडियो बनाने में भी उनका योगदान अहम था। पीएम मोदी जब 2014 में सत्ता में आए तो जिन चंद लोगों से सबसे पहले प्रभावित हुए, उनमें अकबरुद्दीन भी हैं। 2015 में जब वह विदेश सेवा से रिटायर हुए तो पीएम मोदी उन्हें अपने साथ पीएमओ का हिस्सा बनाना चाहते थे। उन्हें पीएमओ का प्रवक्ता बनाने की मंशा भी जाहिर की, लेकिन अकबरुद्दीन ने यूएन में एक बार फिर पोस्टिंग की चाहत दिखाई तो पीएम तुरंत मान गए।

सैयद अकबरुद्दीन
स्थायी प्रतिनिधि, यूएन

वेटनरी डॉक्टर से आईएएस तक

शाहिद इकबाल चौधरी आजकल न सिर्फ अपने, बल्कि केंद्र सरकार के भी सबसे कठिन काम को अंजाम दे रहे हैं। ट्विटर पर शाहिद किसी भी अफवाह को रियल टाइम काटते हैं। किसी को मदद की जरूरत होती है तो तुरंत रिस्पांस देते हैं। घाटी में जब अचानक नए घटनाक्रम के चलते स्थिति तेजी से बदली और पूरे विश्व की नजर इस इलाके पर आई, शाहिद ने सुनिश्चित किया कि संवादहीनता की स्थिति न आए। वह सरकार के सबसे मुखर और प्रखर आवाज बने हैं। 2009 में वह यूपीएससी की परीक्षा में 51वीं पोजीशन प्राप्त कर सिविल सर्विस में आए। वह एलओसी पर स्थित एक छोटे से गांव से हैं और इस सेवा में आने वाले जम्मू कश्मीर राज्य में गुर्जर मुस्लिम समुदाय के पहले व्यक्ति हैं। शाहिद की पढ़ाई जम्मू में हुई। वेटनरी डॉक्टर बने। बाद में इंडिया फॉरेस्ट सर्विस में सिलेक्ट होकर अपने ही राज्य को चुना। लेकिन असली चाहत सिविल सर्विस में चुनकर लोगों की सेवा करने की थी, जो 2009 में पूरी हुई। जम्मू के रिमोट इलाके में रेहान गांव के शाहिद के पिता राज्य सरकार के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में थे। बचपन में 16 किलोमीटर दूर स्कूल पढ़ने के लिए जाना होता था। शाहिद ने अंग्रेजी वर्णमाला 12 साल के बाद पहली बार सुनी। लेकिन बाद में वह देश की सबसे कठिन परीक्षा पास करने में सफल रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके काम से प्रभावित रहे हैं। पिछले पांच साल में उन्हें दो बार गवर्नेंस के स्तर पर केंद्र सरकार की ओर से सम्मान मिला। बेटी बचाओ कार्यक्रम में उनके प्रयासों को भी सराहना मिली थी। कठुआ में बतौर डीसी उन्होंने जो काम किया, उसकी सराहना पीएम मोदी ने सार्वजनिक मंच से की। वहां उन्होंने प्रॉजेक्ट सहायता तब शुरू की थी जब 2014 में पाकिस्तान की ओर से जारी लगातार फायरिंग के कारण लगभग बीस हजार लोगों को सीमा से हटाकर सुरक्षित जगहों तक समय पर ले जाया गया था। उन्होंने उग्रवाद प्रभावित इलाके में लोगों को मुख्यधारा में लाने की बड़ी मुहिम छेड़ी और 2014 आम चुनाव में वोट देने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे उनके जिले में 33 फीसदी से बढ़कर 81 फीसदी वोटिंग हुई। लोगों से सीधे जुड़कर काम करना उनकी ताकत बनी और श्रीनगर में सबसे कठिन हालात में अपनी इसी खूबी की बदौलत वह सरकार के संकट मोचक के रूप में सामने आए हैं।

शाहिद इकबाल चौधरी
डिप्टी कमिश्नर, श्रीनगर

रीडर्स मेल

www.edit.nbt.in

कड़े कानून का समय

16 अगस्त का संपादकीय 'बड़े हौसलों की उड़ान' पढ़ा। प्रधानमंत्री ने लाल किले से बढ़ती जनसंख्या पर जो चिंता जताई है, उस पर सबको चिंतन करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट में बताया है कि अगले 30 वर्षों में विश्व की जनसंख्या दो अरब तक बढ़ सकती है और अगले लगभग 8 वर्षों में जनसंख्या के मामले में भारत दुनिया में नंबर एक बन सकता है। जनसंख्या वृद्धि के लिए गरीब या अशिक्षित ही नहीं, बल्कि पढ़े-लिखे वे अमीर भी जिम्मेदार हैं जो कई रूढ़ियों को पाल रहे हैं। अब समय आ चुका है कि सरकार जनसंख्या पर कड़े कानून बनाए।

राजेश कुमार चौहान, ईमेल से

निरंकुश होता चीन

संपादकीय 'हांगकांग का हंगामा' (14 अगस्त) को पढ़ा। लोकतंत्र के अभ्यस्त हो चुके हांगकांग के लोग पिछले 2 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं। चीन की विस्तारवादी एवं निरंकुश नीति के खिलाफ ये लोग अपना काम-धंधा छोड़कर धरना दे रहे हैं। वैसे विरोध का तात्कालिक मुद्दा प्रत्यर्पण बिल है। इस बिल को वैसे तो निलंबित कर दिया गया है, फिर भी प्रदर्शन रुक नहीं रहा। दरअसल हांगकांगवासी चीनी नीतियों से भयभीत हैं। ब्रिटेन से जब 1997 में हांगकांग का स्वामित्व चीन को मिला था तो 2047 तक यथास्थिति बनाए रखने का समझौता हुआ था। चीन ने उस समझौते का उल्लंघन किया है। विश्व बिरादरी को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए।

जंग बहादुर सिंह, ईमेल से

बुरे दौर में कांग्रेस

जिस तरह मोदी-शाह की जोड़ी संसद में एक के बाद एक बड़े बिल आसानी से पास करा ले रही है, उसे देखकर कांग्रेस अपने किए पर पछताने के अलावा कुछ और नहीं कर सकती। बीजेपी को यह रास्ता भी कांग्रेस ने ही दिखाया है। अपने वक्त में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने विपक्षी एकता को तोड़कर कई बिल पास कराए थे। आज जब कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है तो बीजेपी उसी के फार्मूले का इस्तेमाल करके कई महत्वपूर्ण बिल पास करा रही है। यह कांग्रेसी फार्मूला ही है जिससे अमित शाह विपक्षी एकता ध्वस्त कर रहे हैं। समय कांग्रेस को आईना दिखा रहा है।

मशाहिद अब्बास, ईमेल से

nbteditpage@gmail.com पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।

अंतिम पत्र

'आप' के बगावती रहे कपिल मिश्रा ने बीजेपी जॉइन की - एक खबर
- उन्होंने भी बहती गंगा में हाथ धो ही लिया।

राम मूरत 'राही'

वर्ष 73, संख्या 197

आर.एन.आई. नं. 510/57© सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति के बिना संपूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित। स्वत्वाधिकारी बैनेट, कोलमैन एण्ड कम्पनी लिमिटेड के लिए राजीव यादव द्वारा, 7 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित तथा टाइम्स ऑफ इंडिया प्रेस, साइट IV, औद्योगिक क्षेत्र साहिबाबाद तथा प्लॉट नंबर 407, तिवारीगंज, फैजाबाद रोड, चिनहट, लखनऊ-227105 और प्लॉट नंबर 7-8, सेक्टर M-11, ट्रांसपोर्ट हब, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, मानेसर, हरियाणा से मुद्रित। फोन : 23302000 फैक्सः 23492047, पंजीकृत कार्यालय : दादाभाई नौरोजी रोड, मुंबई-400001। विमान सेवा शुल्क : 1 रु. प्रति कापी। नेपाल में कुल मूल्य : सोमवार से शनिवार : नेपाली 5 रु. ; रविवार : नेपाली 6 रु.

कार्यकारी संपादक (दिल्ली मार्केट) : ए.पी.एस. खाती (इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी)